बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 191

निर्यात और विदेशी बाजार

घरेलू मांग में कमी आने पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं निर्यात बाजारों की ओर रुख करती हैं। तेज गति से विकास करने वाला हर देश सफल निर्यातक होता है। हाल के वर्षों में देश में जो मंदी आई है उसकी बुनियादी वजहों में से एक है निर्यात को गति प्रदान करने में नाकामी। जीडीपी के संदर्भ में निर्यात में तेजी से गिरावट आई है। निर्यात को गति दिए बिना अर्थव्यवस्था मंदी से नहीं उबर सकती। सारी बातचीत आयात प्रतिस्थापन और शुल्क दरों में इजाफा करने के इर्दगिर्द केंद्रित है।

शंकालुओं का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कारोबार मंदा है, ऐसे में निर्यात के प्रति जोश जगाना मुश्किल है। परंतु हमारे देश में वस्त्र व्यापार भी स्थिर है। जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया में तेज निर्यात वृद्धि देखने को मिली है। बांग्लादेश भी भारत से आगे है। इसकी वजह यह है कि ये देश चीन की कमी पूरी कर रहे हैं। चीन हर महीने 20 अरब डॉलर मूल्य के वस्त्र निर्यात करता था जो अब घटकर 12 अरब डॉलर रह गया है (भारत को यह आंकड़ा पाने में नौ महीने लगते)। इस कमी को पूर्वी एशिया के देश और बांग्लादेश पूरा कर रहे हैं। भारत के पास इसका बहुत मामूली हिस्सा आया है। बांग्लादेश का निर्यात भारत के निर्यात का 60 फीसदी हुआ करता था लेकिन अब यह उलट कर दोगुना हो चुका है। वियतनाम भी हमसे काफी आगे हो गया है। विडंबना यह है कि बांग्लादेश कपास, धागा और कपड़ा भारत से आयात करता है। वस्त्र निर्यात, व्यापार घाटे को कम करता है, साथ ही कई जटिल समस्याओं को भी हल करता है। किसी भी अन्य बड़े औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में यह रोजगार को अधिक बढ़ावा देता है। वाहन या इंजीनियरिंग क्षेत्र की तुलना में यह 10 गुना तक और रसायन तथा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की तुलना में 100 गुना अधिक रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग की बिक्री का काफी हिस्सा वेतन-भत्तों में जाता है जो घरेलू खपत की मांग को बढ़ावा देता है। इस क्षेत्र के अधिकांश कर्मी महिलाएं हैं जिनकी श्रम शक्ति में कम होती भागीदारी चिंता का विषय बन चुकी है। चूंकि कपड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र पहले ही कुल विनिर्माण रोजगार के एक तिहाई के बराबर है इसलिए वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने मात्र से विनिर्माण को जबरदस्त गति मिलेगी। अभी भी अवसर समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि चीन के निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क वृद्धि (अभी वस्त्र क्षेत्र पर लागू नहीं) के खतरे के अलावा बढ़ती लागत और घटते मार्जिन से जूझना पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी दिक्कत समुचित परिस्थितियों का अभाव है। बांग्लादेश अत्यंत कम विकसित देश है और उसे यूरोप, कनाडा और जापान के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच हासिल है। वियतनाम और श्रीलंका को भी मुक्त व्यापार समझौतों के तहत यूरोप में ऐसी पहुंच प्राप्त है। यूरोप में बांग्लादेश की शुल्क मुक्त पहुंच 2024 में समाप्त हो जाएगी लेकिन वह मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। अत्यंत कम मार्जिन वाले कारोबार में शुल्क दर में 10 फीसदी की बाधा से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार को संतुलित किया है लेकिन जापानी कार कंपनियों की लॉबीइंग के चलते भारत मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर सका है। सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है और भविष्य निधि खातों में योगदान के जरिये भी उसने बांग्लादेश के साथ वेतन का अंतर कम किया है। नई विनिर्माण इकाइयों के लिए 17 फीसदी की कर दर की पेशकश के साथ यह अंतर और कम हुआ है। परंतु निर्यातकों को कमजोर बुनियादी सुविधाओं और बंदरगाहों पर समय खपाऊ प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ रहा है। रुपये के अधिमूल्यन में सुधार भी उतना ही अहम है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार में कहा है कि वह यह नहीं समझ पा रहे कि सस्ता रुपया कैसे मददगार होगा जबकि देश का व्यापार घाटा खासा बढ़ा हुआ है। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सन 1996 में रुपये के अवमूल्यन के बाद व्यापार के आंकड़ों में समय के साथ सुधार आया जबकि आयात कम हुआ। चार वर्ष में भारी भरकम व्यापार घाटा 80 फीसदी तक पूरा हो गया था। सन 1991 के अवमूल्यन के पहले पांच वर्ष का औसत व्यापार घाटा निर्यात का 40 फीसदी था लेकिन अवमूल्यन के बाद इसमें गिरावट आई और तकरीबन दशक भर तक यह काफी कम बना रहा। आज उतनी तीव्र गिरावट संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका उन देशों पर नजर रखता है जिनके बारे में उसे लगता है कि वे मुद्रा दर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। परंतु इससे निपटने के और भी तरीके हैं। निर्यात वृद्धि जल्द हासिल करने के लिए रुपये का तत्काल अवमूल्यन आवश्यक है।

अजय मोहंती

राहत के कदमों से लौटेगी अर्थव्यवस्था में जान!

मौद्रिक कदम के साथ राजकोषीय उपाय भी किए जाने से आर्थिक वृद्धि एवं कंपनियों के लाभ में तेजी आने की संभावना बढ़ी है। हालात की पड़ताल कर रहे हैं आकाश प्रकाश

वित्त मंत्री ने गत सप्ताह शुक्रवार को कॉर्पोरेट कर में कटौती की घोषणा कर सबको अचरज में डाल दिया। सरकार ने सभी घरेलू कंपनियों की दर में 10 फीसदी तक की कटौती कर उसे 25 फीसदी के स्तर पर लाने का फैसला किया है। वहीं नई विनिर्माण इकाइयां अगर 31 मार्च, 2023 तक चालू हो जाती हैं तो उन्हें 17 फीसदी की प्रभावी दर से ही कर देना होगा। इसके पहले सरकार शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में बदलाव और शेयरों की खरीद एवं बिक्री पर होने वाले पूंजीगत लाभ पर देय अधिभार खत्म करने की भी घोषणाएं कर चुकी है। इन कर रियायतों पर कुल 1.45 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। कॉर्पोरेट कर राहत की मात्रा एवं रफ्तार भारत के लिए अप्रत्याशित है। रातोरात हम एशिया के अधिकांश देशों की बराबरी में पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर यह एक अप्रत्याशित कदम था और शेयर बाजारों ने भी पांच फीसदी से अधिक तेजी हासिल कर इसका जश्न मनाया। भावी परिप्रेक्ष्य में यह साफ हो जाता है कि यह ऐलान एक बड़ा नीतिगत कदम है। निवेशकों को दीर्घकालिक असर के हिसाब से सोचना है और यह केवल कॉर्पोरेट आय बढ़ोतरी का ही मामला नहीं है। इस मुद्दे पर मेरे मन में उठने वाले कुछ सवाल इस तरह हैं:

1. सरकार ने आखिरकार कांग्रेस के 'सूट-बूट की सरकार' वाले तंज से अपना पीछा छुड़ा लिया है। अब यह उद्योग जगत को लुभाने की कोशिश करते हुए दिखने से डरती नहीं है। अगर नैतिक तरीके से पैसे कमाए जाएं तो इसका जश्न होना चाहिए, न कि लानत-मलानत। यह उस धारणा को दुरुस्त करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है कि सरकार कुछ ज्यादा वामपंथी हो चली थी और कारोबार-अनुकूल नहीं रह गई थी।

इस कर राहत के निशाने पर भारतीय कंपनी जगत है और कंपनियों का भरोसा बढ़ाना इसका लक्ष्य है। सरकार ने माना है कि कॉर्पोरेट दिग्गजों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति हावी है। कंपनी अधिनियम में वर्णित कुछ खास अपकृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना भी इसी का हिस्सा है। ब्याज दरों में कितनी भी कटौती कर ली जाए, अगर कंपनी प्रमुखों के मन में भरोसा नहीं है तो निवेश नहीं बढ़ सकेगा।

इन कदमों से भारत कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनेगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में राहत देने से उपभोग को बढ़ावा मिलता लेकिन वित्त मंत्री ने इस उम्मीद में कंपनियों की आय एवं नकदी प्रवाह बढ़ाने की पहल की है कि कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा और वे निवेश से नए रोजगार सृजित करेंगी। भारत में कारोबार चलाने से जुड़े गतिरोधों को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है फिर भी यह एक बड़ा कदम है। अब कर की दरें भारत में निवेश न करने की वजह नहीं रह जाएंगी। कंपनी जगत को अब शिकायती तेवर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और अर्थव्यवस्था एवं इसकी वृद्धि पर दांव लगाना चाहिए। कंपनी जगत के प्रति सरकार की मंशा को लेकर संदेह जताने का वक्त खत्म हो चला है। उम्मीद है कि कंपनियां इस आकस्मिक लाभ का उपयोग भविष्य- लोग, कीमत, तकनीक, ब्रांड निर्माण, संयंत्र या मशीनरी के लिए निवेश में करेंगी। आखिर, घरेलू निवेश को ही अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए, विदेशी निवेश तो केवल सोने पर सुहागा है।

2. वृद्धि पर बहुत बड़ा दांव लगा है। हम निश्चित रूप से इस साल के राजकोषीय लक्ष्य से चूक जाएंगे लेकिन इस कदम का औचित्य तभी साबित हो सकेगा जब वृद्धि पटरी पर आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामाजिक कार्यक्रम चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। नई दरें लागू होने के बाद अगर वृद्धि में तेजी नहीं आती है तो फिर उनके पास सामाजिक योजनाओं के लिए फंड नहीं रह जाएगा। इन कर कटौतियों के बाद आर्थिक वृद्धि को लेकर सरकार की चिंताओं के बारे में सारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। हर कोई इस पर एकजुट है कि तीव्र आर्थिक वृद्धि आज की अनिवार्यता है। बेहतर बात यह है कि राजकोषीय एवं मौद्रिक प्राधिकारी दोनों ही आखिर एक तरफ हैं।

3. मंदी की बात करने वाले राजकोषीय स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यह सच है कि इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.7-3.8 फीसदी तक जा सकता है। हालांकि एक इक्विटी निवेशक के तौर पर मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा अगर वृद्धि तेज हो और आय बढ़े। मैं शून्य मुद्रास्फीति और कमजोर वृद्धि के दौर में राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी रहने के बजाय मजूबत जीडीपी और आय वृद्धि के साथ बढ़े राजकोषीय घाटे को तरजीह दूंगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकार पर परिसंपत्तियों की तीव्र एवं रणनीतिक बिक्री का दबाव भी बढ़ेगा। रणनीतिक विनिवेश फिर से चर्चा में लौटेगा। और वह पहले की तुलना में अधिक आक्रामक होगा। हम खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का तीव्र क्रियान्वयन देख सकते हैं क्योंकि व्यय पर लाभ बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा।

4. हम सूचीबद्ध कंपनियों के कर-पश्चात लाभ में 8-10 फीसदी की उछाल देखेंगे। शुरुआती लाभ कम होगा क्योंकि कुछ कंपनियां नई व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेंगी और दूसरी कंपनियों को विलंबित कर संपत्तियां चिह्नित करनी होंगी। नई कर प्रणाली से इक्विटी पर मिलने वाला सामान्य प्रतिफल बढ़ेगा और कंपनियों के पास अधिक नकद प्रवाह होगा। ये लाभ चिरस्थायी होंगे और इससे बाजार का सैद्धांतिक ढांचा बढ़ेगा।

5. इन कदमों से कंपनी जगत में जारी मजबूती की प्रक्रिया और तेज होगी। मजबूत कंपनी और अधिक मजबूत होगी जबकि कमजोर कंपनी बाहर होती जाएगी। आखिर, अधिकतम दर से कर देने वाली कंपनियां ही इन कदमों का सर्वाधिक लाभ लेंगी। लाभ में नहीं चल रही अशक्त कंपनियों को इस व्यवस्था से फायदा नहीं होगा। कमजोर परिचालन या खस्ता बहीखाते वाली कंपनियां लुप्त होती जा रही हैं जिससे बेहतर संचालित कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिल रहा है। इन कटौतियों के बाद भारतीय कंपनी जगत में सफाई का दौर तेज होगा।

6. संक्षिप्त अवधि में अर्थव्यवस्था कमजोर बनी रहेगी। दूसरी तिमाही में कंपनियों की आय के आंकड़े डराएंगे, उपभोग मांग दुरुस्त होने में वक्त लगेगा, एनबीएफसी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, निवेश में फौरी तेजी नहीं दिखेगी और रोजगार वृद्धि कमजोर बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में लोग यह सवाल उठाने लगेंगे कि सरकार के इन राहत उपायों का कोई असर नहीं हुआ है और आयकर एवं जीएसटी की दरों में कटौती करना कहीं बेहतर होता। कुछ लोग कहेंगे कि कंपनियां इन लाभों को दबाकर बैठ जाएंगी।

वैसे मेरी राय में धारणा बदल गई है। ऐसा ही बाजारों के साथ हुआ है। सरकार ने दिखाया है कि वह सुनने को तैयार है और उसके लिए अर्थव्यवस्था एवं कंपनी जगत मायने रखते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण में खाली जगह भर दी गई है। सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़े दांव लगाने की मंशा भी दिखाई है। निवेशकों को लगा था कि मौद्रिक नीति ही अर्थव्यवस्था में जान डालने का इकलौता जरिया है। लेकिन हम गलत थे। किसी ने भी इतनी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं की थी। अब मौद्रिक एवं राजकोषीय दोनों उपायों को एक साथ आजमाया जा रहा है। अगले 18 महीनों में जीडीपी एवं कंपनी मुनाफा दोनों में तेजी की उम्मीद की जाए। शायद हम दोनों मामलों में निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं।

(लेखक फंड प्रबंधन फर्म अमांसा कैपिटल के साथ जुड़े हैं)

ओटीटी प्लेटफॉर्म से भारतीय कहानियों को मिल रहा विस्तार

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

क्या भारतीय कहानियों को दुनिया में अपना मुकाम मिल गया है? पिछले हफ्ते दो भारतीय शो और एक फिल्म को चार अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के लिए नामित किया गया। (ये पुरस्कार हाल ही में घोषित एमी पुरस्कारों से अलग हैं।) भारत से सेक्रेड गेम्स-1 (ड्रामा सीरीज), लस्ट स्टोरीज (टीवी मूवी/मिनी सीरीज), राधिका आप्टे (सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, लस्ट सीरीज) और द रीमिक्स-इंडिया (नॉन-स्क्रिप्ट मनोरंजन) नामित हुए हैं। विजेताओं के नाम की घोषणा 25 नवंबर को की जाएगी।

क्या हम आखिरकार भारतीय परिवेश में बुनी गई भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों की स्वीकृति मिलते हुए देख रहे हैं? क्या क्रॉसओवर कंटेंट की तलाश खत्म हो गई है?

पिछले साल 6 जुलाई को मराठी एवं पंजाबी के घालमेल वाला हिंदी शो सेक्रेड गेम्स एक साथ 190 देशों में मौजूद 12.5 करोड़ ग्राहकों के मोबाइल फोन पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ था। इस ऑनलाइन शो की समीक्षा दुनिया के हरेक बड़े समाचार संस्थान ने की थी, चाहे वह द गार्डियन हो या द न्यूयॉर्क टाइम्स। इसके पहले किसी भी भारतीय टीवी शो या फिल्म को इस तरह की वैश्विक रिलीज नहीं मिली थी। यह ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाने वाला पहला मौलिक भारतीय शो था और यह देखते ही देखते जबरदस्त लोकप्रिय हुआ। लस्ट स्टोरीज को लेकर इतनी चर्चा नहीं हुई लेकिन इसे भी नेटफ्लिक्स पर इसी तरह की रिलीज मिली थी।

मुंबई स्थित प्रोडक्शन हाउस ग्रेमैटर एंटरटेनमेंट का बनाया शो द रीमिक्स 10 टीमों की मौजूदगी वाला एक फॉर्मेट शो है जिसमें हरेक टीम में एक डीजे, गायक, प्रोड्यूसर और डांसर होते हैं। सभी टीमें अगले 10-15 हफ्तों तक एक-दूसरे से मुकाबला करती रहीं। इस शो को वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। द रीमिक्स-इंडिया एमेजॉन प्राइम वीडियो पर पिछले साल एक साथ 200 देशों में स्ट्रीम हुआ था।

इन ऑनलाइन शो को उस तरह की रिलीज मिली जिसके लिए भारतीय फिल्म स्टूडियो वर्षों तक तरसते रहे हैं। लेकिन उनके पास न तो उस तरह का कंटेंट था और न ही इतने बड़े पैमाने पर रिलीज के लिए विपणन एवं वितरण की ताकत ही थी। लेकिन अब यह एक मानक बन चुका है। एमेजॉन प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुए शो द फैमिली मैन का प्रीमियर लॉस एंजलिस में हुआ। इंटरनैशनल एमी अवॉर्ड के लिए तीन भारतीय शो और अभिनेत्री राधिका का नामित होना और दर्शक जुटाने एवं पुरस्कार के लिए ब्राजील एवं ब्रिटिश कार्यक्रमों से मुकाबला करना भारतीय कंटेंट की काबिलियत के बारे में भरोसा जगाने वाली बात है।

सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म पथेर पांचाली (1955) न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू इलाके में स्थित प्लेहाउस सिनेमाघर में लगातार 226 दिनों तक प्रदर्शित हुई थी। इसने अमेरिका में किसी विदेशी फिल्म के सबसे लंबे समय तक प्रदर्शन का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। बाद में राज कपूर की फिल्मों ने रूस के लोगों को खूब लुभाया था। नब्बे के दशक में सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन (1994) फिल्म से ब्रिटेन एवं अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के दिल को छू लिया था। उसके अगले ही साल आई आदित्य चोपड़ा की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और करण जौहर की फिल्मों 'कुछ कुछ होता है' (1998) और 'कभी खुशी कभी गम' (2001) ने प्रवासी भारतीयों के बीच भारतीय फिल्मों को और मजबूती दी। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी बाजार भी भारतीय फिल्मों की बिक्री का एक क्षेत्र बन गए। जर्मनी या पेरू जैसे देशों में शाहरुख खान की फिल्में पसंद करने वाले कुछ स्थानीय लोग भी होते थे लेकिन मुख्य रूप से यह प्रवासी भारतीयों का ही बाजार था। विदेशी बाजारों में मुख्यधारा वाली फिल्मों के प्रदर्शन और दर्शकों के बीच किसी तरह का क्रॉसओवर नहीं था।

हालांकि 2006-07 तक कॉर्पोरेट अंदाज ने भारतीय फिल्म कारोबार को बदल दिया था। बड़े स्टूडियो दस्तक दे चुके थे और घरेलू फिल्म बाजार भी अधिक स्क्रीन एवं टेलीविजन के प्रसार के चलते काफी व्यापक हो चुका था। इस स्थिति में भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता भी सुधरी और ओमकारा या रंग दे बसंती (2006) जैसी फिल्मों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन गुजरे दौर को सुनहरा मानने वाले विदेशी बाजार को इस तरह की असलियत के करीब लगने वाली फिल्में अधिक पसंद नहीं आई और यह बाजार सिकुड़ने लगा।

फिर तीन ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने भारतीय कहानियों के लिए बाजार मौजूद होने की धारणा पुख्ता कर दी। इनमें सबसे पहले 2008 में प्रदर्शित डैनी बॉएल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर थी। भले ही यह फिल्म भारतीय नहीं थी लेकिन यह भारत के ही बारे में थी। राजकुमार हिरानी की फिल्म 3ईडियट्स (2009) और नितेश तिवारी की फिल्म दंगल (2016) पूरी तरह भारतीय मिजाज और भारतीय अंदाज में परोसी गई कहानियां थीं। इन दोनों ही फिल्मों ने चीन में खूब पैसे कमाए जो भारतीय फिल्म कारोबार के लिहाज से एकदम अनूठी बात थी। बाद में बजरंगी भाईजान (2015) और सीक्रेट सुपरस्टार (2017) भी चीन में खूब सफल रहीं। भारतीय फिल्मों को लेकर विदेशी बाजारों के रवैये में आए इस बदलाव को हॉलीवुड और वहां के बड़े स्टूडियो ने भी संज्ञान में लिया। वर्ष 2016 में इंटरनेट डेटा की दरें सस्ती होने तक भारत का रचनात्मक परिवेश अगली छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुका था। ओरिजिनल कंटेंट के लिए 35 ओटीटी प्लेटफॉर्मों के बीच जंग छिड़ चुकी थी जो भारतीय कंटेंट तैयार करने वाले निर्माताओं के लिए जश्न मनाने वाली बात थी। ओरिजिनल कंटेंट की मांग तेज होने का अर्थ है कि लेखकों, फिल्मकारों, तकनीकी कामों में कुशल लोगों की विशाल फौज रखने वाला भारत आखिरकार रचनाधर्मी पहलू पर काम करने लगा है जबकि नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म इन कहानियों को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं।

कानाफूसी

होगी घर वापसी?

क्या समाजवादी पार्टी (सपा) और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया (पीएसपीएल) अपने मतभेद समाप्त करने को तैयार हैं? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसा संकेत दिया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि सभी पार्टी नेता और परिवार के सभी सदस्य जो पार्टी से दूरी बना चुके हैं, उन सबका वापस स्वागत है। पीएसपीएल का गठन अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने किया था। इस पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। इस दौरान इन दोनों दलों ने एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाया। हालांकि घर वापसी की चर्चा में पार्टी का सपा में विलय करना भी शामिल है लेकिन पीएसपीएल ने शिवपाल की घर वापसी की किसी भी संभावना से इनकार किया है। बहरहाल अखिलेश के बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

हिज्जों की चूक

यह सही है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ नेता संवाद की प्राथमिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सच यह भी है कि कई भाजपा शासित राज्यों में ही चीजें सही ढंग से नहीं चल रही हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल थे। कार्यक्रम में बैनर में युग प्रवर्तक शब्द ही गलत लिखा हुआ था। यह कार्यक्रम महायोगी गोरखनाथ पर आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन था। गोरखनाथ की शिक्षाओं पर ही नाथ संप्रदाय आधारित है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुखिया भी हैं।

आपका पक्ष

कीनिया से सबक लेने की जरूरत

भारत प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश नहीं है फिर भी वह इसके इस्तेमाल के खिलाफ जन आंदोलन तैयार कर रहा है। इससे वह एक पर्यावरण हितैषी और चिंतक के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। आज जिस तरह आम जनजीवन में प्लास्टिक का 80 प्रतिशत इस्तेमाल हो चुका है वहां इस पर रोक लगाना मुश्किल है। लेकिन यह समय के साथ असंभव नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। रोजाना हम प्लास्टिक का एक बार ही इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं। इससे वह नालियों के जरिये नदी में फिर समुद्र में पहुंच जाता है। आज समुद्र कचरे का डंप यार्ड बनता जा रहा है। हमें कीनिया जैसे छोटे देश

से सीख लेनी होगी जहां वर्ष 2002 में ही प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कुछ कार्य किए जा सकते हैं। इसमें दूध, बिस्कुट, नमकीन आदि को प्लास्टिक की पैकिंग के बजाय इसका विकल्प खोजना चाहिए।

एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है

प्लास्टिक के कप, कटोरी, प्लेट, चम्मच, बर्तन आदि पर पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है। प्लास्टिक प्रबंधन के लिए उचित नियम बनाए जाने चाहिए। कंपनियां जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाती हैं उन्हें वापस लेने का उचित प्रबंध करना चाहिए। लोगों को प्लास्टिक के बदले जूट या कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए।

शिव द्विवेदी, बक्सर

गोरखपुर में भी बढ़ने लगा प्रदूषण

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण हालत गंभीर होती जा रही है। इसी तरह गोरखपुर में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण गोरखपुर भी दिल्ली के समान होता जा रहा है। आने वाले दिनों में पर्व-त्योहार मनाए जाएंगे। दशहरा, दीवाली, छठ पूजा, एकादशी व्रत आदि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर में प्रदूषण नियंत्रण का खास ख्याल रखने की जरूरत है। यहां कचरे का सही निपटान नहीं होने के कारण सड़क के किनारे कचरे का टीला दिखाई देने लगा है। इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बीमारियां पैदा होने लगी हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए नगरपालिका को जगह-जगह साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन नदी तालाबों में नहीं करना चाहिए। पटाखों की बिक्री पर भी नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि इनसे वायु तथा ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। लोगों को प्रदूषण कम करने में सहयोग करना चाहिए।

राजू, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।